गुना जिला

नवभारत

भोपाल, बुधवार 19 नवम्बर, 2025

एक नजर में

चौधरी मोहल्ला में घर के बाहर से बाइक चोरी

गुना। शहर के चौधरी मोहल्ला क्षेत्र में देर रात घर के बाहर खड़ी बाइक चोरी होने का मामला सामने आया है। फरियादी कमल सिंह कुशवाह ने सिटी कोतवाली पहुंचकर बताया कि गत सुबह अपने रिश्तेदार राजू कुशवाह की मोटरसाइकिल से खेत राम टेकरी के पास गया था। शाम को खेत से लौटने के बाद वह रात करीब 9 बजे अपने घर पहुंचा और बाइक को घर के बाहर खड़ा कर दिया। कमल सिंह के अनुसार रात करीब एक बजे जब उसने बाहर आकर देखा, तो मोटरसाइकिल मौके से गायब थी। आसपास तलाश करने के बावजूद बाइक का कोई पता नहीं चला। चोरी हुई मोटरसाइकिल हीरो सीडी डीलक्स क्रमांक एमपी 08-0347 है, जिसे अज्ञात चोर उठा ले गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है, ताकि चोरों तक पहुंचा जा सके।

पुरानी रंजिश में युवक पर फर्से से हमला

गुना। जिले के आरोन थानांतर्गत टंकपरोरिया गांव में रविवार रात पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक पर फर्से से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। फरियादी ज्योतिराज अहिरवार ने बताया कि उसका भाई जगदीश रात करीब 8.30 बजे घर लौट रहा था, तभी पहलवान अहिरवार के घर के पास विनोद अहिरवार ने उसे रोककर गालियां देना शुरू कर दीं। मना करने पर विनोद ने सिर, हाथ और पैर पर फर्से से वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। शोर सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे तो आरोपी धमकी देते हुए भाग गया। घायल को उपचार के लिए आरोन अस्पताल में भर्ती कराया गया.

शिक्षा के मंदिर में ठूंस-ठूंस कर लोडिंग वाहनों से ढोया जा रहा देश का भविष्य

फतेहगढ़ क्षेत्र के हाल, मोटी कमाई के केंद्र बने निजी स्कूल, सुविधाओं के नाम पर जीरो

नवभारत न्यूज

गुना। ग्रामीण अंचल में शिक्षा के नाम पर चल रहे निजी विद्यालयों की मनमानी और शिक्षा विभाग की अनदेखी अब आपराधिक बनती जा रही है। फतेहगढ़ क्षेत्र में कई निजी स्कूल मोटी कमाई के केंद्र बन गए हैं, जहाँ बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इन विद्यालयों में न तो ज़रूरी सुविधाएँ हैं, न सुरक्षित भवन, और तो और देश के भविष्य यानी मासूम छात्रों को प्रतिदिन जान जोखिम में डालकर लोडिंग वाहनों और ऑटो रिक्शा में ठुस-ठुस कर ढोया जा रहा है। सुविधाओं के अभाव के बावजूद शिक्षा विभाग द्वारा इन्हें आसानी से मान्यता प्रदान कर दी गई है, जो इस पूरे तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

सुविधाओं का घोर अभाव, फिर भी मान्यता मेहरबान:

नव भारत की पड़ताल में फतेहगढ़ में चार ऐसे निजी विद्यालय सामने आए हैं, जिनमें खेल ग्राउंड तक नहीं है। भवन के नाम पर चार-पाँच कमरों में माध्यमिक स्तर तक की कक्षाएँ संचालित की जा रही हैं। 10 से 15 किमी दूर से आने वाले बच्चों को इन जर्जर ढाँचों में ज्ञान दिया जा रहा है। सबसे गंभीर विषय है छात्रों का असुरक्षित परिवहन। छोटे ऑटो रिक्शा और माल ढोने वाले लोडिंग वाहनों में क्षमता से अधिक बच्चों को भरकर लाने-ले जाने का यह ख़तरनाक सिलसिला बेखौफ जारी है। यह सीधे-सीधे बच्चों की सुरक्षा और सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों का उल्लंघन है।

देख लूंगा की धमकी, संचालक की दबंगई और विभाग की चुप्पी जब संवाददाता ने छबड़ा चौराहे पर एक ऑटो रिक्शा में ठुंसे हुए 15-20 बच्चों की तस्वीरें लीं और हकीकत जाननी चाही, तो स्कूल संचालक मनोज राजपूत भड़क उठे। उन्होंने फोन पर संवाददाता को धमकाते हुए कहा कि वह 15 साल से स्कूल चला रहे हैं और मेरे पास आए कोई अधिकारी फिर देखता हूँ। संचालक की यह दबंगई बताती है कि शिक्षा विभाग इन पर कितना मेहरबान है। यह सिर्फ एक स्कूल की नहीं, बल्कि उस पूरे भ्रष्ट तंत्र की कहानी है जहाँ मोटी फीस वसूलने के बावजूद सुरक्षा और सुविधाओं को ताक पर रख दिया गया है और सवाल उठाने पर धमकाया जाता है।

शिक्षा विभाग की चुप्पी, कार्रवाई क्यों नहीं?

स्पष्ट है कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों की अनदेखी और मनमाना रवैया ही ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे अवैध व सुविधाविहीन विद्यालयों को फलने-फूलने का मौका दे रहा है। बिना खेल ग्राउंड और असुरक्षित परिवहन वाले इन स्कूलों को मान्यता देना विभाग की कार्यप्रणाली पर एक बड़ा धब्बा है। यदि समय रहते इन पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई, तो बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा का स्तर लगातार गिरता रहेगा, और मुनाफाखोरों के केंद्र बन चुके ये निजी विद्यालय देश के भविष्य को ख़तरे में डालते रहेंगे। इस संबंध में जब जिला शिक्षा अधिकारी श्री गोयल से संपर्क किया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया।

अतिक्रमण से परेशान ऑटो चालक जनसुनवाई में कलेक्टर से कार्रवाई की मांग

गुना। शहर में ऑटो स्टैण्डों पर बढ़ते अतिक्रमण को लेकर मंगलवार को बड़ी संख्या में ऑटो चालक जनसुनवाई में पहुंचे और कलेक्टर को आवेदन देकर तुरंत कार्रवाई की मांग की। आवेदकों ने बताया कि नगर पालिका द्वारा अम्बेडकर चौराहा, पीजी कॉलेज रोड स्थित सीसीआई पार्क के कॉर्नर पर आधिकारिक रूप से ऑटो स्टैण्ड निर्धारित किया गया है, जहां बोर्ड भी लगाया गया है। लेकिन पिछले कुछ समय से यहां ठेले और गुमठी वालों ने अवैध कब्जा कर लिया है। चालकों का कहना है कि दोपहर बाद दूध वाले, बर्गर-पेटीज विक्रेता और नाश्ता ठेले वाले स्टैण्ड पर कब्जा जमा लेते हैं और ऑटो को हटवाने लगते हैं। इतना ही नहीं, वे अपने ग्राहकों की मोटरसाइकिल, स्कूटी और कारें भी वहीं खड़ी करवाते हैं। विरोध करने पर झगड़ा करने और गुंडे बुलाने की धमकी तक दी जाती है, जिससे ऑटो चालकों की रोजी-रोटी प्रभावित हो रही है। ऑटो चालकों ने कलेक्टर से मांग की कि सीसीआई पार्क-कॉलेज रोड-अम्बेडकर चौराहा क्षेत्र में लगे अतिक्रमण को तुरंत हटाया जाए, ताकि भविष्य में किसी अनहोनी की स्थिति न बने और ऑटो चालकों को उनके निर्धारित स्थान पर काम करने में सुविधा मिल सके। अधिकारियों ने आवेदन प्राप्त कर मामला जांचने का आश्वासन दिया।

कब्ज़े और मारपीट से पीड़ित जाटव परिवार ने जनसुनवाई में लगाई गुहार:

इधर जनसुनवाई में मंगलवार को ग्राम धमनार के दिमानसिंह जाटव और जगनू जाटव ने अपनी भूमि पर से जबरन कब्ज़ा हटवाने की मांग को लेकर कलेक्टर को आवेदन सौंपा। आवेदकों ने बताया कि सर्वे क्र. 35/4 रकबा 1.0660 हे. का सीमांकन 30 जून 2025 को हो चुका है।

खाली टोकन थमाने से भड़के किसान, जताया विरोध

गुना। जिले में खाद वितरण व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेर में आ गई है। मंगलवार को बड़ी संख्या में किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे और अधिकारियों के खिलाफ विरोध जताया। किसानों का कहना था कि उन्हें खाली टोकन थमा दिए गए, जिन पर न तो नाम दर्ज था, न पिता का नाम, न ही तारीख या पहचान संबंधी कोई विवरण। बिना नाम वाले इन टोकनों के कारण खाद वितरण केंद्रों पर उनकी एंट्री दर्ज नहीं हो पा रही, जिससे भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने बताया कि केंद्रों पर सुबह 3 बजे से ही लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, लेकिन व्यवस्था पूरी तरह अव्यवस्थित है और अधिकारी स्पष्ट जानकारी तक देने को तैयार नहीं हैं।

मुरादपुर क्षेत्र से आए ग्रामीणों ने बताया कि वे रात 3 बजे से एमपी एग्रो कार्यालय के बाहर लाइन में लगे थे। घंटों इंतजार के बाद जब टोकन मिले तो वे खाली निकले। किसानों का कहना है कि संबंधित अधिकारियों ने यह भी नहीं बताया कि खाद कब मिलेगी। सिर्फ इतना कहा गया कि रोज आकर देखते रहो, होगा तो दे देंगे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि करीब दो सौ से अधिक किसानों को ऐसे ही बिना नाम और तारीख वाले टोकन दे दिए गए। इससे किसानों में भारी नाराजगी फैल गई और वे सामूहिक रूप से कलेक्ट्रेट पहुंचकर शिकायत दर्ज कराने मजबूर हुए।

वहीं, मौके पर मौजूद किसानों ने यह भी बताया कि अव्यवस्था के बीच धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई और एक युवक के साथ मारपीट की कोशिश तक की गई। ग्रामीणों का कहना है कि खाद की कमी और खराब प्रबंधन के चलते किसानों को कई दिनों से परेशानी झेलनी पड़ रही है। समय पर खाद न मिलना रबी सीजन की बुवाई पर भी असर डाल रहा है।

कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई : वाहन चेकिंग के दौरान पकड़े गए दो कुख्यात बाइक चोर, दो बाइक भी कीं बरामद

नवभारत न्यूज

गुना। पुलिस अधीक्षक अंकित सोनी के निर्देश पर जिले में चल रही सघन वाहन चेकिंग अभियान के दौरान गुना कोतवाली पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। हरिपुर रोड पर सोमवार शाम की गई चेकिंग के दौरान बिना नंबर प्लेट की हीरो सीडी डीलक्स बाइक पर सवार दो संदिग्ध युवकों को रोकने पर पुलिस को उन पर संदेह हुआ। दस्तावेज मांगने पर दोनों युवक गोल-मोल जवाब देने लगे, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की। पूछताछ में युवकों ने अपना नाम धर्मेंद्र उर्फ मुर्गा लोधा निवासी उमरिया रोड, और लोकेन्द्र लोधा निवासी पुरानी छावनी गुना बताया। दोनों ने कबूल किया कि जिस मोटरसाइकिल पर वे पकड़े गए,

उसे उन्होंने 16-17 नवंबर की रात चौधरी मोहल्ला से चोरी किया था। वाहन के इंजन और चेसिस नंबर की जांच में बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर एमपी 08-0347 पाया गया, जो फरियादी कमल सिंह कुशवाह की चोरी हुई मोटरसाइकिल निकली।

आगे पूछताछ में आरोपी धर्मेंद्र ने खुलासा किया कि पिछले वर्ष जुलाई में एचडीएफसी बैंक के सामने से चोरी की गई प्लेटिना मोटरसाइकिल भी उसी ने चुराई थी। यह मोटरसाइकिल एमपी 30- 5623 भी आरोपियों के कब्जे से बरामद कर ली गई है। इन घटनाओं को लेकर गुना कोतवाली में क्रमशः अप.क्र. 623/25 और 17/25 धारा 303(2) बीएनएस के अंतर्गत प्रकरण दर्ज थे। पुलिस द्वारा दोनों ही मामलों में चोरी हुई बाइकें अब बरामद कर ली गई हैं और आरोपियों को हिरासत में लेकर अन्य वारदातों के संबंध में पूछताछ जारी है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी धर्मेंद्र उर्फ मुर्गा लोधा आदतन अपराधी है, जिसके खिलाफ चोरी, लूट, डकैती की तैयारी, मारपीट, आर्म्स एक्ट, आबकारी एक्ट और एससी-एसटी एक्ट सहित कुल 13 प्रकरण गुना कोतवाली और कैंट थाना क्षेत्रों में दर्ज हैं। इस सफल कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक सी.पी.एस. चौहान, उपनिरीक्षक विजय गुड़सले, आरक्षक नरेन्द्र रघुवंशी, जितेंद्र सिंह, विनय धाकड़, दीपेश रावत और सैनिक रंजीत समर की विशेष भूमिका रही।

एसआईआर सर्वे व निर्वाचन ड्यूटी के विरोध में आशा-उषा

कार्यकर्ताओ ने कलेक्टर पहुंचकर दिया ज्ञापन

गुना। एसआईआर सर्वेक्षण में जबरन लगाए जा रहे दबाव और निर्वाचन संबंधी ड्यूटी को लेकर नाराज आशा-ऊषा एवं सहयोगी कार्यकर्ता मंगलवार को कलेक्टोरेट पहुंचे। यहां उन्होंने जनसुनवाई में आवेदन देकर स्पष्ट कहा कि स्वास्थ्य विभाग के पूर्व आदेश के बावजूद बीएलओ और पंचायत सचिवों द्वारा लगातार धमकी दी जा रही है कि यदि वे एसआईआर सर्वेक्षण नहीं करेंगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्यकर्ताओं ने कहा कि रात में प्रसूताओं की डिलेवरी कराने के बाद सुबह उन्हें सर्वेक्षण के लिए भेजना अमानवीय है। इससे पहले सोमवार को सभी आशा-ऊषा कार्यकर्ता जिला अस्पताल गेट के सामने शास्त्री पार्क में एक

दिवसीय धरने पर बैठीं थीं। उन्होंने प्रोत्साहन राशि, बकाया वेतन, कार्यभार में पारदर्शिता और अनियमितताओं को दूर करने की मांग उठाई। मोर्चा से जुड़ी जिलाध्यक्ष मिथलेश गोस्वामी ने बताया कि बीएलओ व सचिवों द्वारा दी जा रही धमकियों से कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश है। कई जिलों में तीन-तीन महीनों से भुगतान नहीं हुआ है, जिससे त्यौहारों के दौरान भी परिवार चलाना मुश्किल हो गया।

धरने में प्रमुख मांगें थीं सभी बकाया वेतन व प्रोत्साहन राशि का तत्काल भुगतान, केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाई गई राशि का एरियर सहित वितरण, हर माह की 5 तारीख तक नियमित भुगतान और सभी भुगतान की पर्ची जारी करना, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि समस्याओं का तुरंत निराकरण नहीं किया गया तो 17 नवंबर को प्रदेशभर में 24 घंटे का बड़ा आंदोलन किया जाएगा।

स्वास्थ्य विभाग का पूर्व आदेश

धरने में कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा 21 जून 2023 को जारी उस आदेश का हवाला भी दिया, जिसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि आशा कार्यकर्ता शासकीय कर्मचारी नहीं हैं, वे स्वैच्छिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, इसलिए उनकी ड्यूटी किसी भी प्रकार के निर्वाचन कार्य में नहीं लगाई जाए। आदेश में यह भी उल्लेख था कि निर्वाचन कार्यों में लगाने से मातृ-शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, परिवार नियोजन और अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रम गंभीर रूप से प्रभावित हो सकते हैं। आज जनसुनवाई में आशा-ऊषा कार्यकर्ताओं ने इसी आदेश की प्रति सौंपकर निर्वाचन ड्यूटी से मुक्त करने की मांग दोहराई।

बेरखेड़ी में पारदी युवकों पर हमला, घायल

गुना। जिले के धरनावदा थाना क्षेत्र के ग्राम बेरखेड़ी में सोमवार दोपहर रास्ता रोककर एक युवक पर लुहांगी और लाठी से हमला करने का मामला सामने आया है। फरियादी सुल्तान पारदी, निवासी मुरादपुर चक, ने जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में पुलिस को दिए बयान में बताया कि दोपहर करीब 1 बजे वह अपने पड़ोसी ज्वाला पारदी के साथ राशन लेने मोटरसाइकिल से बेरखेड़ी जा रहा था। जैसे ही वह गांव में प्रकाश खैरुआ की आटा चक्की के पास पहुंचा, तभी राजाबाबू पारदी और राहुल पारदी ने मोटरसाइकिल अड़ाकर उसका रास्ता रोक लिया। दोनों ने उसे च्मुरादपुर चक में पारदियों का नेता बननेज् के ताने देते हुए गालियां देना शुरू कर दिया। विरोध करने पर राजाबाबू ने लुहांगी से उसके सिर पर लगातार दो वार किए, जिससे गंभीर चोटें आईं है।

ईंट भटट् की आग बुझने का डर, अडानी की फैक्ट्री के लिए पुनर्वास किए बिना बेदखली के नोटिस से हड़कंप

गुना। जिला मुख्यालय से लगे मावन के करैया क्षेत्र में दशकों से ईंट भट्टा लगाकर अपनी रोज़ी-रोटी चलाने वाले कुम्हार-प्रजापति समाज के परिवार इन दिनों गहरी चिंता और असुरक्षा में हैं। प्रशासन की ओर से हाल ही में जारी बेदखली नोटिस ने इन गरीब परिवारों की नींद उड़ा दी है। जिस भूमि पर वर्षों से उनकी मेहनत की गूंज सुनाई देती रही, अब वही जमीन अडानी ग्रुप की प्रस्तावित सीमेंट फैक्ट्री के लिए आवंटित कर दी गई है, और ईंट भट्टे चलाने वाले परिवारों को वहां से हटने का आदेश दे दिया गया है। समाज के मनोज प्रजापति बताते हुए भावुक हो उठे कि शासन ने उन्हें पहले इसी क्षेत्र में ईंट निर्माण के लिए करीब दो हेक्टेयर जमीन दी थी। आधा सैकड़ा परिवार दिन-रात मेहनत कर ईंट बनाते हैं और लगभग तीन हजार मजदूरों का पेट इसी काम से भरता है। लेकिन अब अचानक उन्हें अतिक्रमणकारी बताया जा रहा है। अगर हमें यहां से बिना दूसरी जमीन दिए हटा दिया गया, तो सैकड़ों परिवार सडक़ पर आ जाएंगे। हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा? भट्टा संचालकों का कहना है कि पिछले पाँच-छह महीनों में कई बार नोटिस मिले, पर हर बार प्रशासन ने आश्वासन दिया कि यदि जमीन खाली कराई गई तो उसके बदले दूसरी जगह — करीब 40 बीघा दी जाएगी, ताकि वे अपना काम जारी रख सकें। लेकिन आज तक उन्हें कागज पर एक इंच जमीन भी नहीं दी गई। परिवारों का कहना है कि वे प्रशासन का विरोध नहीं कर रहे, बस इतना चाहते हैं कि उन्हें बिना

वैकल्पिक जगह दिए उजाड़ा न जाए।

तहसीलदार द्वारा जारी नोटिस में स्पष्ट लिखा है कि सर्वे नंबर 679/1/6/1 की करीब 5 हेक्टेयर भूमि अडानी सीमेंट प्लांट के लिए आवंटित है और ईंट भट्टा लगाना भू-राजस्व संहिता की धारा 248 के तहत दंडनीय है। परिवारों को 18 नवंबर तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है, अन्यथा बेदखली की कार्रवाई होगी। ईंट भट्टा संचालकों और मजदूरों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि जब तक दूसरी जगह आवंटित न हो, बेदखली न की जाए, क्योंकि यह मुद्दा सिर्फ जमीन का नहीं, बल्कि हजारों लोगों के जीवन, परिवारों की सुरक्षा और आने वाली पीढय़िों के भविष्य का है। वे कहते हैं— अडानी की फैक्ट्री बने, हमें कोई आपत्ति नहीं लेकिन हमारी दुनिया उजाडक़र नहीं।

उपलब्धि — रेन वॉटर हार्वेस्टिंग में गुना देश में नंबर-1

राष्ट्रपति ने नपाध्यक्ष और प्रभारी सीएमओ को दिया राष्ट्रीय सम्मान

नवभारत न्यूज

गुना। पर्यावरण संरक्षण और जल प्रबंधन के क्षेत्र में गुना नगर पालिका परिषद ने ऐसा इतिहास रचा है, जिसकी गूंज अब राष्ट्रीय स्तर पर सुनाई दे रही है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के मामले में देशभर में प्रथम स्थान प्राप्त कर गुना ने मध्यप्रदेश का नाम रोशन किया है। मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुना नगरपालिका को सम्मानित किया। यह प्रतिष्ठित अवॉर्ड नपाध्यक्ष सविता अरविंद गुप्ता और प्रभारी सीएमओ तथा डिप्टी कलेक्टर मंजुषा खत्री ने मंच पर जाकर ग्रहण किया। नगर पालिका ने केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लक्ष्य के मुकाबले रिकॉर्ड सिस्टम स्थापित कर कीर्तिमान कायम किया।

इसके लिए निकाय को 40 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि भी प्राप्त होगी। यह उपलब्धि नगर पालिका के सामूहिक प्रयास, जनभागीदारी और मजबूत नेतृत्व का परिणाम मानी जा रही है। उल्लेखनीय है कि गुना के इतिहास में पहली गुना नगरपालिका को राष्ट्रपति पुरस्कार का सम्मान मिला है। जो शहरवासियों के लिए गौरव की बात है। इसी के चलते भीषण गर्मी में भी विगत तीन सालों से गुना शहर पेयजल संकट की त्रासदी से बचता रहा है।

नपाध्यक्ष सविता गुप्ता एवं सीएमओ के नेतृत्व में जल संरक्षण को लेकर पिछले एक वर्ष में विशेष अभियान चलाया गया। उनकी पहल पर जल संचय जनभागीदारी योजना के तहत नपाध्यक्ष सविता अरड्क्षवद गुप्ता, कलेक्टर किशोर कन्याल और प्रभारी सीएमओ मंजुषा खत्री के मार्गदर्शन में विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई। इसके बाद इंजीनियरों और फील्ड कर्मचारियों की कई टीमें गठित की गईं, जिन्हें स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सरकारी भवन, निजी कॉलोनियां, मल्टीस्टोरी बिल्डिंग्स सहित पूरे निकाय क्षेत्र का सर्वे कर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की वास्तविक स्थिति का आकलन करने की जिम्मेदारी दी गई।

सर्वे के बाद पाया गया कि कई स्थानों पर सिस्टम तो मौजूद थे, लेकिन उनमें मरम्मत या सुधार की आवश्यकता थी। नपाध्यक्ष सविता गुप्ता की पहल पर और सीएमओ के निर्देशन में नगर पालिका ने जनसहयोग से इन सभी सिस्टमों को दुरुस्त करवाया। एक सप्ताह में रिकॉर्ड सिस्टमों के जियो-टैग फोटो पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए, जो पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। साथ ही 10 से 15 पुराने कुओं का जीर्णोद्धार कर उन्हें पुनर्जीवित किया गया, जो सराहनीय कदम माना जा रहा है। इस उपलब्धि में सहायक यंत्री शैलेन्द्र जी, इंजीनियर नितिन चंदेल, इंजीनियर सुनील जैन, भारती लोधी सहित अन्य नपा के अधिकारी-कर्मचारियों का विशेष योगदान रहा। इनकी मेहनत और टीमवर्क ने गुना को देश के टॉप-50 शहरी निकायों में पहला स्थान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुना नगरपालिका की यह सफलता न केवल जिले के लिए गर्व का विषय है, बल्कि जल संरक्षण के क्षेत्र में पूरे देश के

भारतीय मजदूर संघ ने 46 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

नवभारत न्यूज

गुना। भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में मंगलवार को जिले में विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों को उठाते हुए 46 सूत्रीय ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा गया। ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम संबोधित था, जिसमें प्रदेशभर के नियमित, संविदा, आउटसोर्स और पेंशनभोगी कर्मचारियों से जुड़े प्रमुख मुद्दों को शामिल किया गया। संघ ने विशेष रूप से वेतन विसंगति दूर करने, सभी विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण, आउटसोर्स कर्मचारियों के विभागीय संविलियन तथा बिजली विभाग के टी.ए. बैच 2013 के लंबित मामलों के समाधान की मांग की। साथ ही पेंशनरों की समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया गया।

जिले से भारतीय मजदूर संघ के विभाग प्रमुख धर्मस्वरूप भार्गव, जिला अध्यक्ष कन्हैयालाल ग्वाल, जिला मंत्री दीपक गुप्ता सहित संघ के सभी अनुसांगिक संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बिजली कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष आर.सी. झा के नेतृत्व में राजेंद्र यादव, सुदीप मिश्रा, महेंद्र कुमार शर्मा, कुलदीप सिंह गौतम, अरविंद परमार सहित बड़ी संख्या में बिजली संविदा कर्मचारी भी कलेक्ट्रेट पहुंचे।

न्यायालय अपर कलेक्टर एवं विशेष अधिकारी, जिला गुना

प्रकरण क्रमांक 0071/स-149/2025-26

विज्ञप्ति

आवेदकगण प्रधुमन सिंह धाकड़ पुत्र श्री गजानंद धाकड़ (आयु 27 वर्ष) निवासी ग्राम बालाभेंट तहसील राघौगढ़ जिला गुना (म.प्र.) एवं पूजा प्रजापति पुत्री श्री किशन प्रजापति (आयु 25 वर्ष) निवासी ग्राम गोंदलपुर तहसील राघौगढ़ जिला गुना (म.प्र.) द्वारा आधार कार्ड, शपथ पत्र तथा उचित शीर्ष में 100 रूपये का चालान आदि दस्तावेज पेश कर मय साक्षियों सहित विशेष अधिनियम 1954 की धारा-5 के तहत आशयित विवाह कराये जाने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया है।

यदि किसी व्यक्ति को इस विवाह के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई शिकायत अथवा आपत्ति हो तो वह इस संबंध में दिनांक 01.12.2025 तक अपनी आपत्ति अपर कलेक्टर एवं विवाह अधिकारी जिला गुना के कार्यालय में कार्यालयीन समय प्रातः 10:00 बजे से 06:00 बजे तक दर्ज करा सकते हैं। नियत दिवस व्यतीत होने पर किसी प्रकार की शिकायत/आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी।

(अखिलेश कुमार जैन)
अपर कलेक्टर एवं
विशेष विवाह अधिकारी, जिला गुना (म.प्र.)